भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4522
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

बीएसएनएल के विकास की योजना

4522. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के विकास को बढ़ावा देने, उनके उपभोक्ता अनुभव में सुधार लाने और इसके राजस्व में वृद्धि करने के लिए कोई योजना/रणनीति तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने बीएसएनएल के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोई उच्च स्तरीय कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठक की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैठक के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत आगामी वर्षों के लिए राजस्व वृद्धि का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
(ङ) बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति और प्रचालन कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए अन्य क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार उल्लिखित हैं :

- वर्ष 2019 में, लगभग 69 हजार करोड़ रुपये की राशि का पहला पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया गया जिससे बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रचालन लागत कम हो गई।
- वर्ष 2022 में, लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये की राशि का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया गया। इसमें नए सिरे से पूंजी निवेश, ऋण के पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- वर्ष 2023 में, सरकार ने लगभग 89 हजार करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से बीएसएनएल को 4जी/5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अनुमोदन प्रदान किया।
- वर्ष 2025 में पूरे देश में बीएसएनएल द्वारा 4जी नेटवर्क के रोलआउट के लिए अतिरिक्त कैपेक्स सहायता के रूप में अतिरिक्त 6,982 करोड़ रुपए के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इन पैकेजों के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2020-21 से प्रचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है।

(ख) से (घ) बीएसएनएल के शीर्ष अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर उच्च स्तरीय कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। इन विचार-विमर्शों में दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की भूमिका को सुदृढ़ करने, अवसंरचना के रोलआउट में तेजी लाने, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने, विकास और आधुनिकीकरण आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ङ) आत्मनिर्भर भारत पहल की तर्ज पर, बीएसएनएल ने अखिल भारतीय संस्थापना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 4जी साइटों के लिए क्रय आदेश जारी कर दिया है। 4जी उपकरणों की आपूर्ति सितंबर 2023 से शुरू हो गई है और दिनांक 31.07.2025 तक कुल 96,300 4जी साइट संस्थापित की गई हैं और 91,281 साइट ऑन एयर हैं। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उपकरण का 5जी में उन्नयन किया जा सकता हैं।

नेटवर्क अवसंरचना और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीएसएनएल सरकार की विभिन्न स्कीमें जैसे 4जी सेचुरेशन स्कीम, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)/ बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट (बीआईपी) आदि का निष्पादन कर रहा है। इन स्कीमों का विवरण https://usof.gov.in पर उपलब्ध है।

*****